

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,

प्रमुख सचिव

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,

उद्यान भवन चौबटिया-रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक, 07 अक्टूबर 2015

विषय-चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में "सेब" का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उद्यान विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 879 XVI-1/15/5(29)/2015 दिनांक 20 अगस्त 2015 के क्रम में, राज्य में सेब फसल के उत्पादकों को उनकी उपज का अपेक्षित मूल्य प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपर्युक्त विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु राज्य में उत्पादित सी-ग्रेड सेब फसल हेतु रु 7000.00 प्रति मैट्रिक टन (रु 7.00 प्रति किलो) की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए कृषकों/फल उत्पादकों से क्रय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. सेब के उपार्जन हेतु घोषित उपरोक्त मूल्य कुल अनुमानित मात्रा 2500 मै0टन अथवा वास्तविक मात्रा जो भी कम हो, की सीमान्तर्गत अनुमन्य होगा एवं उक्त उपार्जन का कार्य जनपद उत्तरकाशी, नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून एवं चमोली में स्थापित उद्यान विभाग के यथोचित संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से किया जायेगा। सम्बन्धित जनपदीय केन्द्रों पर जिला उद्यान अधिकारियों द्वारा यथोचित विभागीय कार्मिकों की तैनाती तथा मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
2. उक्त सेब का उपार्जन कार्य दिनांक 31 अक्टूबर 2015 की अवधि तक प्रभावी होगा।
3. योजना केवल उद्यान कार्डधारक उद्यानपतियों हेतु प्रभावी होगी। ठेकेदार एवं बिचौलिये इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे। क्रय किये जाने वाले "सी" ग्रेड सेब फल का न्यूनतम आकार 50 मि0मी0 व्यास से कम नहीं होना चाहिए, एवं फल आंशिक सड़े-गले, कटे, फटे नहीं होने चाहिए एवं फसल पुनः विक्रय योग्य होनी चाहिए। फल 20 किग्रा0 क्षमता के प्लास्टिक क्रेट्स में उद्यानपतियों से प्राप्त किये जायेंगे।

तुड़ाई उपरान्त फलों में वाष्पीकरण एवं श्वसन क्रिया के परिणामस्वरूप वजन में होने वाली कमी के दृष्टिगत उपार्जन क्रय के समय तौल में 2.5 प्रतिशत अधिक वजन लिया जायेगा।

4. उक्त उपार्जन का कार्य उद्यान विभाग, एवं विभाग के अन्तर्गत संचालित उत्तराखण्ड औद्यानिक विपणन बोर्ड के सहयोग से किया जायेगा, उक्त कार्य में आवश्यकता पड़ने पर अन्य संस्थाओं यथा कुमांऊ मण्डल विकास निगम एवं गढ़वाल मण्डल विकास निगम का सहयोग प्राप्त किया जाय। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यापक प्रचार प्रसार, सुनिश्चित किया जाय,
5. सम्बन्धित उत्पादकों को उपरोक्त घोषित समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होने की स्थिति में वे अपनी फसल का विक्रय करने हेतु स्वतंत्र होंगे। उद्यान विभाग द्वारा उपार्जित सेब को भण्डारणोपरांत अथवा ताजे उपार्जित फलों को राज्य के भीतर तथा बाहर स्थापित मण्डियों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की प्रसंस्करण इकाईयों को विक्रय किया जायेगा यदि समर्थन मूल्य या इससे अधिक मूल्य स्थानीय बाजारों में प्राप्त होता है तो इसे नीलामी द्वारा प्रथम प्राथमिकता पर विक्रय किया जायेगा। फलों के विक्रय से प्राप्त आय को सम्बन्धित सुसंगत लेखाशीर्षक में तत्काल जमा किया जायेगा एवं सम्पूर्ण भुगतान एकाउन्ट पेई चैक के माध्यम से किया जाय।
6. उक्त उपार्जन कार्य का सम्पूर्ण क्रियान्वयन नियमानुसार उद्यान विभाग के अन्तर्गत संचालित उत्तराखण्ड औद्यानिक विपणन बोर्ड को चक्रीय निधि के रूप में स्वीकृत रु 10.00 करोड़ की धनराशि से किया जायेगा एवं विभाग द्वारा क्रय/उपार्जित "सी" ग्रेड सेब के उपार्जन कार्य में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।
7. उक्त आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के आ0श0 पत्र संख्या 39/NP/XXVII-4/15 दिनांक 01.10.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

11/10/2015
(डा० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।

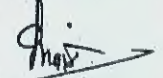
कमश:-3

संख्या- /XVI-1/15/5(29)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, गोपन (मंत्रीपरिषद्) अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़/देहरादून/उत्तरकाशी/चमोली।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
6. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. उप निदेशक, उद्यान विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
9. जिला उद्यान अधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़/देहरादून/उत्तरकाशी/चमोली।
- ✓ 10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड औद्योगिक विपणन परिषद्, देहरादून।
12. निजी सचिव, मा0 उद्यान मंत्री जी उत्तराखण्ड सरकार।
13. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
14. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव वन एवं ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(टीकम सिंह पंवार)
अपर सचिव।

